जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 119 प्रभात जालोर, रविवार 4 अगस्त, 2024 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

## कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ नया फ्रंट खोला, चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में हेराफेरी का

### कांग्रेस का आरोप है, लोकसभा चुनाव में भाजपा 79 सीटें मतदान प्रतिशत में हेराफेरी करके जीती है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अगस्त। कांग्रेस पार्टी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर लोडेड मिसाइल दागी है और मतों में हेराफेरी करके फर्जी जीत हासिल करने का आरोप लगाया है।

यह आरोप लगाते हुए कि 2024 आम चुनावों में, कुल मतदान संख्या में हेराफेरी करके भाजपा ने 79 सीटों पर विजय हासिल की है, कांग्रेस ने आज भारतीय चुनाव आयोग से, प्रारंभिक तथा फाइनल मतदान आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।

वोटर फॉर डैमॉक्रेसी (वी.एफ.डी.) की एक रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रैंस में कहा कि, चुनाव आयोग ने शुरु में जो कहा और अंत में जो आंकड़े दिए उसमें समग्र अंतर औसतन 4.7 प्रतिशत है, लेकिन पूरे राष्ट्र में मिलाकर ये 5 करोड़ वोट होते हैं।

- **कांग्रेस के अनुसार, 2019 में मतगणना प्रारम्भिक रूप से घोषित मतदान प्रतिशत व फाइनल वोटिंग परसैन्टेज में केवल एक प्रतिशत का फर्क था, पर, 2024 में प्रारम्भिक मतदान प्रतिशत व फाइनल घोषित मतदान प्रतिशत में औसतन 4.7 प्रतिशत का फर्क था, जो जायज नहीं लगता।**
- **कांग्रेस के अनुसार, ओडीशा व आंध्र, जहाँ भाजपा को मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशित सफलता मिली है, वहाँ, प्रारम्भिक व फाइनल में, 12.5 प्रतिशत का फर्क है और लक्षद्वीप में तो यह फर्क 25 प्रतिशत है।**
- **कांग्रेस का यह भी कहना है कि मतदान के बाद चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित करने में इतना अधिक समय लगाना भी संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि, आधुनिक टैक्नोलॉजी से तो मतगणना के समय हर दो घंटे में वोटों की संख्या अपडेट होती है, पर, चुनाव के प्रथम चरण के वोटिंग के आंकड़े देने में चुनाव आयोग को 11 दिन लगे थे।**

वी.एफ.डी. रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने खुलासा किया कि ओडीशा तथा आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य, जहाँ भाजपा व उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा रहा, प्रारंभिक तथा फाइनल मतदान आंकड़ों में अंतर 12.5 प्रतिशत का, जो कि बहुत बड़ा अंतर है तथा चुनाव आयोग को इसका, जवाब देना चाहिए।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि एक प्रतिशत का अंतर तो समझ में आता है, लेकिन 12.5 प्रतिशत का भारी अंतर तथा लक्ष्यद्वीप जैसी जगहों पर 25 प्रतिशत तक का अंतर गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है।

रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट ने विशेष रूप से उन 79 निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहाँ भाजपा जीती है, वहाँ पर अंतिम मतदान प्रतिशत, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए प्रारंभिक आंकड़ों से बहुत ज्यादा बढ़ गया।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## 2023 में 2.16 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अगस्त। कांग्रेस ने आज भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पर भारतीयों द्वारा नागरिकता छोड़े जाने के मुद्दे पर कटाक्ष किया और कहा कि मौजूदा सरकार के तहत जो भय का माहौल बना है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सरकार के अपने आंकड़े जो उसने राज्यसभा में जारी किए हैं, बताते हैं कि वर्ष 2023 में 2.10

- **राज्यसभा में प्रस्तुत इस सरकारी आंकड़ें पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा और कहा कि भय के माहौल व कर प्रणाली के कारण भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं।**

लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है जोकि 2016 में 1.23 लाख भारतीयों का दोगुना है।

उन्होंने दावा किया कि जिन भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है वे कुशल एवं उच्च शिक्षित हैं और देश के कुशल श्रम आपूर्ति की कमी के समय इनके देश छोड़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

रमेश ने कहा कि इनमें से कई लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न भी है। इस साल

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## वित्तीय बाज़ार में कमला हैरिस की बढ़ती साख ने ट्रम्प की चिंता बढ़ाई

### मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल में ट्रम्प की भागीदारी की वैल्यू 900 मिलियन डॉलर घट गई है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अगस्त। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में डैमोक्रेटिक पार्टी की नई प्रत्याशी कमला हैरिस को वित्तीय बाजार बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। डॉनल्ड ट्रम्प के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" की वैल्यू में आयी भारी कमी से इसका संकेत मिल सकता है।

ट्रुथ सोशल में ट्रम्प की भारीदारी की मार्केट कैपिटल में 900 मिलियन डॉलर तक की कमी आई है। बाइडन के कमला हैरिस के पक्ष में पीछे हटने से पहले तक ट्रम्प की भागादारी 4 अरब डॉलर तक थी अब यह घटकर 3.1 अरब डॉलर रह गई है।

ऐसा माना जाता है कि अगर ट्रम्प राष्ट्रपति बन गए तो यह मंच उनकी सोशल मीडिया पोस्टिंग का जरिया बन जाएगा और इसी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई थी।

लेकिन कमला हैरिस के डैमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी के रुप में राष्ट्रपति पद की दौड़ में सामने आने के बाद से ट्रुथ सोशल के साथ ट्रम्प के जुड़े होने की वैल्यु वित्तीय बाजार में कम हो रही है। वो राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडन की तुलना में ज्यादा मजबूत उम्मीदवार के रुप में सामने आई हैं, यह बात ट्रम्प की जीत की संभावना के खिलाफ जा रही है।

- **जब से डैमोक्रैटिक प्रत्याशी के रूप में कमला हैरिस का नाम सामने आया है, वित्तीय बाजार में ट्रम्प की साख कम हो रही है।**
- **इससे ट्रम्प काफी हताश हो रहे हैं। हाल ही में अश्वेत पत्रकारों से वार्ता करते हुए ट्रम्प कई बार आपा खो बैठे, जिससे उनकी हताशा के संकेत मिल रहे हैं।**

कमला हैरिस ने डैमोक्रेटिक अभियान में और सभी प्रमुख डैमोक्रेटिक नेताओं में जोश भर दिया है। जो पहले हैरिस के खिलाफ थे वे भी उनके पक्ष में आ गए हैं। कुछ श्वेत समूह भी कमला हैरिस को समर्थन दे रहे हैं।

हैरिस को इन दिनों बड़ी सफलता मिली जब युनाइटेड ऑटो वर्कर्स, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, ने कमला हैरिस की दावेदारी का समर्थन किया।

अपने अभियान के लिए फंड जुटाने में भी हैरिस काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका में फंड जुटाने को प्रत्याशी की लोकप्रियता और जीत का पैमाना माना जाता है। इस सप्ताह के आरंभ में ट्रम्प ने अश्वेत पत्रकारों से बात करते हुए अपने चुनाव अभियान को लेकर हताशा के संकेत दिए। कई सवालों के जवाब में तो वे काफी गुस्सा हो गए थे।

मौजूदा प्रशासन के बारे में भी ट्रम्प ने अपने ही अंदाज में बोला।

रुस में अमेरिकन बंदियों की बहुप्रतीक्षित रिहाई की सफल वार्ता के

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## महाराष्ट्र के चुनाव की गहमा-गहमी चरम पर पहुंची

### उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को टारगैट बनाते हुए कहा कि शाह, अहमद शाह अब्दाली के राजनैतिक उत्तराधिकारी हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अगस्त। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी चुनावी युद्ध की रेखाएं खिंच गई हैं, शिव सेना (यू.बी.टी.) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अहमद शाह अब्दाली के 'राजनीतिक वंशज' हैं।

शिव सेना (यू.बी.टी.) ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि वह सत्ता में बने रहने के लिए 'राजनैति जिहाद" में संलिप्त है तथा इसके लिए वह राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ कर रही है।

पुणे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए ठाकरे ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला और उन्हें "औरंगजेब फैन क्लब" का अध्यक्ष बताया।

ठाकरे ने शाह की आलोचना की और शाह को "अहमद शाह अब्दाली" का 'राजनीतिक उत्तराधिकारी' बताया।

- **असल में अमित शाह ने कुछ अर्सा पूर्व ठाकरे को औरंगज़ेब फैन क्लब का प्रमुख कहा था, इसके जवाब में ठाकरे ने शाह को अब्दाली का वंशज बताया। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था जिसने पानीपत के युद्ध में मराठों को हराया था।**
- **पुणे में शिव सेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सत्ता के बने रहने के लिए भाजपा राजनैतिक "जिहाद" कर रही है और विभिन्न दलों को तोड़ रही है।**

अब्दाली अफगान शासक था, जिसने मराठों को पानीपत के युद्ध में हराया था।

ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की गईं 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' की आलोचना करते हुए कहा कि वह मतदाताओं में "रेवड़ी" बांटकर उन्हें रिश्वत देने का कार्य कर रही है।

ठाकरे ने कहा "जब हमने मुस्लिमों को हमारे हिन्दुत्व के बारे में बताया तो वो हमारे साथ हो गए, इस पर (भाजपा ने) हमें औरंगजेब फैन क्लब कहा। तो जो आप कर रहे हो, वह सत्ता के लिए जिहाद है।"

21 जुलाई को जब शाह महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने महा विकास अघाड़ी गठबंधन को "औरंगजेब फैन क्लब" कह कर उसकी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि ठाकरे इस क्लब के नेता हैं।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## 'कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स की बढ़ती संख्या के लिए नीति बनाई जाए'

-सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3अगस्त। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि भारत में तेजी से बढ़ते हुए कोचिंग संस्थानों के लिए एक समग्र नीति समाधान लाने की जरूरत है और कहा पाठ्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए तथा सभी परीक्षा आयोजकों के पास अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निवेश की जरूरत है।

- **कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 2019 से 2024 के बीच कोचिंग संस्थाओं से होने वाली जी.एस.टी. वसूली 2,241 करोड़ रूपए से बढ़कर 5,517 करोड़ रूपए हो गई है। कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स की बढ़ती संख्या के समाधान की जरूरत है।**

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## सुप्रीम कोर्ट के "कोटा में कोटा" देने वाले निर्णय से राजनैतिक वातावरण बहुत गर्माया

### कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे आरक्षण के माध्यम से सोशल जस्टिस करने के प्रयास पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय का वह निर्णय, जिसमें राज्यों को यह अनुमति दे दी गई है कि वे अनुसूचि जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों में "कोटा के अन्दर कोटा" निर्धारित कर सकते हैं, ने एक बवाल खड़ा कर दिया है। एन.डी.ए. के दो घटक दलों ने इस सम्बन्ध में अपनी चिन्ताएं व्यक्त कर दी हैं। केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिये सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। आर.पी.आई. नेता रामदास अठावले ने भी एस.सी./एस.टी. में क्रीमी लेयर की शर्त को लागू करने की कोशिशों का विरोध किया है। अठावले भी केन्द्रीय मंत्री है।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को पसन्द करने वाले लोगों का कहना है कि क्रीमी लेयर को चिन्हित करके उसे आरक्षण से बाहर करने के दरवाजे खुल जाने से सामाजिक न्याय की मौजूदा नीतियों को एकदम सटीक बनाने के रास्ते की लम्बे समय से चली आ रही बाधायें दूर हो गई हैं। इससे भिन्न एक विचार यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के परिणाम स्वरूप, एस.सी. और एस.टी. श्रेणियों के बीच एक राजनैतिक लड़ाई जन्म लेगी तथा एस.सी./एस.टी. के नौकरी में गारन्टीड आरक्षण राजनैतिक हितों की सनकों पर निर्भर हो जायेगा। एक ताकतवर विचार यह भी है कि इस आदेश के चलते, आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की प्रक्रिया की दिशा में एक शुरुआत हो जायेगी।

- **"कोटा में कोटा" देने की शुरुआत सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार ने की थी, जब उन्होंने दलितों में "महादलित" वर्ग चिन्हित किया था।**
- **एन.डी.ए. के दो घटक दलों के नेताओं, चिराग पासवान और रामदास अठावले ने इस फैसले का विरोध किया व सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही है। चिराग का कहना है कि सदियों से छूआछूत झेल रही जातियों के उत्थान का उद्देश्य इससे पूरा नहीं होगा।**
- **सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करने वाले वर्ग का कहना है कि इससे सामाजिक हकदारों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने की राह में जो भी बाधाएं हैं, सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि क्रीमी लेयर आरक्षण से बाहर हो जाएगी और वास्तविक जरूरतमंद को ही आरक्षण को लाभ मिलेगा।**

प्रसंगवश बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपनाई गई प्रतिक्रियाओं के अनुरूप हैं। नीतीश कुमार ने "महादलित" श्रेणी को चिन्हित करके, उसे दलित श्रेणी की तुलना में सकारात्मक कार्यवाही का कहीं ज्यादा पात्र बताया था। किन्तु कुछ पर्यवेक्षकों का विचार है कि इन मुद्दों का सम्बन्ध केवल नौकरी से ही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद, राज्य सरकारों के लिये यह सम्भव हो सकता है कि वे "सफाई कर्मचारी" वाली जातियों को क्रीमी लेयर श्रेणी में

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## 21 साल से कम उम्र और 40 फीसदी से कम अंक वालों की नियुक्ति पर रोक

जयपुर, 3 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है, जिनकी उम्र एक जनवरी, 2024 को 21 साल से कम थी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोडकर उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं देने को कहा है, जिनके भर्ती की लिखित परीक्षा में चालीस फीसदी से कम अंक हैं। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के संबंध में दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।**

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## पश्चिमी देशों में भारतीय मूल के जाने-माने राजनीतिज्ञ, भारत के लिये खास मददगार साबित नहीं होते!

### वे सदा भारी दबाव में रहते हैं, अपने नये "घर" (नये देश) के प्रति अपनी वफादारी साबित करते रहें और इस जिम्मेवारी में दबे हुए वे सबसे पहले अपने पुराने देश (मातृभूमि) के हितों का बलिदान करते रहते हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अगस्त। विदेशों में भारतीय मूल के राजनेताओं के उदय से वहां के भारतीय समुदाय के प्रभाव और सफलता का पता चलता है, लेकिन यह भारत को आवश्यक लाभ नहीं पहुंचाता। ये नेता अपने राजनीतिक सिस्टम के भीतर ही काम करते हैं और अपने नए देश के हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। अपनी दोहरी पहचान के कारण इन नेताओं पर कड़ी नज़र रहती है, इसलिए ये भारतीय हितों की अपेक्षा अपने गृहीत देश की नीतियों का अधिक अनुसरण करने के बाद अपना रूख तय करते हैं।

कमला हैरिस का अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद तक आरोहण और अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डॉनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ उनका डैमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी बनना एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसका भारतीय और भारतीय अमेरिकन, दोनों जश्न मना रहे हैं। भारतीय मां की पुत्री होने के नाते अमेरिका की राजनीति में उनकी यह उपलब्धि भारतीय अमेरिकियों के लिए एक मील का पत्थर है। तथापि, डैमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील एजेण्डे के कारण बनी उनकी राजनीतिक स्थिति प्रायः भारतीय हितों के अनुकूल नहीं रही है।

- **उदाहरण के लिये, आर्टिकल 370 को सस्पैंड करने के बाद, जब हिन्दुस्तान ने इन्टरनैट पर प्रतिबंध लगाया था, आंतकवादियों को संगठित होकर वारदातें करने से रोकने के लिये, तब अमेरिका की जानी-मानी भारतीय मूल की कांग्रेस मैन प्रमिला जयपाल ने वहाँ की संसद में प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की भारत के खिलाफ। शायद उनका मकसद अमेरिका के विदेश मंत्रालय को "इम्प्रैस" करना था।**
- **इसी तरह का आचरण निक्की हैली, प्रीत भरारा, बॉबी जिंदल व सुएला ब्रोवरमैन का रहा है। बॉबी जिंदल, पहले भारतीय-अमेरिकी थे, जो अमेरिका में गवर्नर बने, अपनी भारतीय विरासत से दूरी बनाकर, ईसाई धर्म अपनाया, अपनी अमेरिकी पहचान को और मजबूत करने के लिए और इसका उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिला, रिपब्लिकन पार्टी में जल्दी से जल्दी एक के बाद एक उच्च पद व जिम्मेवारी पाने में।**

उदाहरण के तौर पर, हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भारत के कृषि कानूनों की आलोचना कर एक कूटनीतिक मुद्दा छेड़ दिया। सोशल मीडिया पर उनकी अलंकारिक भाषा, जिसका उद्देश्य संभवतः प्रगतिशील लोगों का समर्थन जुटाना था, ने उन लोगों को आलोचना की सामग्री प्रदान कर दी ,जो भारत में सुधारों का विरोध कर रहे थे। यहां तक कि अमेरिका की सरकार ने भी उक्त सुधारों का समर्थन किया था। इससे समझ में आता है कि उनके बयान को कमला हैरिस की स्वीकृति थी।

पश्चिमी देशों में भारतीय मूल के राजनेता अपने गृहीत देशों के हितों को नैसर्गिक रूप से प्राथमिकता देते हैं। आज के ध्रुवीकृत वैश्विक राजनीतिक माहौल में, वे अपने नए देशों के प्रति अपनी निष्ठा को साबित करने के लिए प्रायः स्वयं को बाध्य महसूस करते हैं और कभी-कभी तो ऐसा भारत के हितों की कीमत पर होता है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है, अमेरिकी कांग्रेस की प्रमिला जयपाल द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद व्यक्त किए गए विचार। भारत की

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## 'मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं'

जयपुर, 3 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारियों के निधन के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने के दो अलग-अलग मामलों में प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र गुर्जर व राहुल गुप्ता की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने के दो मामलों में प्रमुख शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किये।**

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )